depth performance of public enterprises as well as the factors affecting the performance whenever warranted. These studies aim at removing difficulties arising out of non-satisfactory performance of infrastructure of the enterprises as studies so as to improve utilization of capacity, control costs, improve managerial performance and operation efficiency etc.

(d) The losses suffered by some of the undertakings are sometimes due to external reasons like interruptions in power supply, recession in the market and pricing policies involving conscious decisions to assist weaker sections of the society. As a result of the steps taken, the performance of the public enterprises is expected to show improvement in 1982-83.

FINANCIAL HELP TO TEXTILE MILLS IN MAHARASHTRA AND GUJARAT

3534. SHRI G. NARSIMHA REDDY : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Textile Mills in Gujarat and Maharashtra which are facing the labour strike have urged upon Government for substantial financial help to start the mills as and when the stalemate is over;

(b) if so, the names of the mills and their projected demand;

(c) whether Government have agreed to it; and

(d) if so, the details of the decision taken ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (d) The Bombay Millowners' Association have represented that textile mills in Bombay will, at the time of reopening after the textile workers' strike, require substantial financial help from the banks and financial institutions. No such representation has recently been received from textile mills in Gujarat. It is for the banks and financial institutions to appropriately consider the representations made on behalf of the Bombay-based textile mills in accordance with credit policy and other policy implications. The question of Government providing substantial help to start the mills does not arise.

PUBLIC SECTOR UNDERTAKING UNDER STRIKE

3535. SHRI A. T. PATIL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Heavy Water Plant at Baroda was locked out by the management in the beginning of June, 1982;

(b) the reasons which led to the lock-out of this public sector unit; and

(c) how many public sector units are :—

(i) under strike (ii) under lock-out, and (iii) under closure or closed as on 15th June, 1982 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA) : (a) Yes, Sir. The Lock-out was declared on 6th June, 1982 and was lifted on 26th June, 1982.

(b) The lock-out was on account of labour unrest.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वित्त मंत्रालय द्वारा बेरोजगार युवकों के लिये बनाई गई नई योजना

3536. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने देश में बेरोजगार युवकों के स्व-विकास और स्व-नियोजन के लिए कोई नई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह योजना कब से क्रियान्वित की जाएगी ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) "विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने में बैंकों की भूमिका" का अध्ययन करने के लिए स्थापित किये गये कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने रोजगार बढ़ाने के लिए, ऋण में वृद्धि करने के वास्ते वाणिज्यिक बैंकों की ब्यौरेवार हिदायतें जारी की थी । इन सुझावों के

आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सब बैंकों से निम्नलिखित बातें कहीं थीं :—

(1) बैंकों को समग्रतः वार्षिक आधार पर, इस प्रयोजन के लिए प्रति शाखा दो अतिरिक्त व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। इस के लिए आधार वर्ष 1978 होगा।

(2) क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार विषयक आयोजना के लिए खण्ड (ब्लाक) को एक इकाई माना गया है, बैंकों को उन ब्लाकों के बारे में स्वयं-नियोजन स्कीम के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिनकी विकास योजनाएं तैयार हैं और साथ ही उन्हें अपनी स्कीमों को अन्य ब्लाकों में भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

(3) लीड बैंक योजना के अधीन बनायी गयी जिला स्तरीय परामर्श-दात्री समितियों को बैंकों और विकास अभिकरणों के बीच समन्वय का प्रमुख तंत्र बना रहना चाहिए।

(4) लीड बैंकों द्वारा बनायी गयी जिला ऋण योजनाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि उनसे रोजगार और विकास स्कीमों के सम्बन्ध का स्पष्ट संकेत मिले।

(5) ब्लाक स्तर पर योजना की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके अनुसार ऋण योजना में भी इन समुदायों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और इन समुदायों के व्यक्तियों के लिए विशेष बैंक सहायता की स्कीमें बनायी जानी चाहिएं ताकि ऐसी स्कीमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और आत्म-नियोजन के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि हो सके।

(6) परिचालनात्मक विकास अभिकरणों में बैंकों की प्रभावशाली भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लीड बैंकों के प्रतिनिधियों को इन अभिकरणों की कार्यकारिणी समिति का सदस्य बना दिया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ब्लाक/जिला स्तर के अन्य विकास अभिकरणों की कार्यकारिणी समितियों में लीड बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल करें।

(7) अनुसूचित जाति क्षेत्रों में, अपनी व्याप्ति को बढ़ाने में बैंकों को सामर्थ बनाने के लिए राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि वे वृहद् आकार बहु प्रयोजनीय समितियों (एल०ए०एम० पी०एस०) को बैंकों को सौंपने पर विचार करें।

(8) बैंकों को जिला औद्योगिक केन्द्रों से निकट सम्पर्क स्थापित करना है जोकि विभिन्न जिलों में आत्म-नियोजन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये गये हैं।

(9) आत्म-नियोजन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को पूरा करने के वास्ते प्रत्येक बैंक को विभिन्न स्तरों पर लीड बैंक स्कीम को कार्यान्वित करने के अपने संगठन को मजबूत बनाना चाहिए ताकि बैंकों की शाखाओं की स्कीमें निर्धारित करने, तैयार करने, कार्यान्वित करने और उनके बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करने के बारे में तकनीकी क्षमता सही तरह से निर्मित हो सके। इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ विशेष शाखाओं के लिए संगठनात्मक योजनाएं बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति शाखाओं का दर्जा बढ़ाने और कम स्टाफ वाली शाखाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त हिदायतों के आधार पर बैंकों ने लाभप्रद व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के वित्त पोषण के लिए स्कीमें तैयार की हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंक 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' (आई०आर०डी०पी०) में भाग ले रहे हैं जिसके अधीन पांच वर्षों की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के 1.5 करोड़ परिवारों को 3 हजार करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त होंगे ताकि वे आत्म-नियोजन द्वारा अपनी जीवन दशा को सुधार सकें। बैंक "आत्म नियोजन के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण" (टी०आर०वाई०एस०ई० एम०) में भी भाग ले रहें हैं।

तस्करी की जांच हेतु मोटर नौकाएं

3537. **श्री राम अवध** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ समय पहले